सौराष्ट्र में समेकित बाल विकास सेवा योजनाएं

8394. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र में केन्द्रीय और विदेशी सहायता से चलाई जा रही समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान, उक्त योजना के अधीन आवंटित की गई धन-राशियों का ब्लॉक-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक इन योजनाओं की उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में स्वीकृत आई सी डी एस परियोजनाओं की कुल संख्या 148 हैं, जिनमें आई सी डी एस की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सौराष्ट्र में संस्वीकृत 46 परियोजनाएं भी शामिल हैं । इन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता यूनिसेफ से सामान के रूप में उपलब्ध होती हैं जैसे जीपें तथा तोलने की मशीनें आदि ।

(ख) केन्द्रीय सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत ब्लॉक-वार अथवा जिला-वार राशि निर्मुक्त नहीं करती । स्कीम के अन्तर्गत, 14.56 लाख रुपये प्रति परियोजना की दर से अनुमोदित पद्धति के अनुरूप राज्य सरकारों को राशि निर्मुक्त की जाती है । गुजरात राज्य सरकार को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान, क्रमशः 1496.87 लाख तथा 2210.17 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सौराष्ट्र में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम

क्र.सं.	जिले का नाम	आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या
1992-93		
1	2	3
1.	अमरेली	10
2.	भावनगर	8
3.	जामनगर	10
4.	जूनागढ़	6
5.	राजकोट	11
6.	सुरेन्द्रनगर	8
1993-94		
1.	अमरेली	10
2.	भावनगर	8
3.	जामनगर	10
4.	जूनागढ़	6
5.	राजकोट	1
6.	सुरेन्द्रनगर	

1994-95

1	2	3
1.	अमरेली	10
2.	भावनगर	9
3.	जामनगर	10
4.	जूनागढ़	7
5.	राजकोट	12
6.	सुरेन्द्रनगर	8

Sub-Standard Private Sports Colleges

3395. PROF. VJJAY KUMAR MALHOJRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a great gap in the requirement and availability of teachers in Physical Education and Sports and that sub-standard private colleges are growing at a rapid pace, as reported in a section of Press that about 205 new colleges of Physical Education which have been started in Maharashtra alone during 1993-94; and

(b) if so, what are the steps being taken by Government to check the phenomenon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) Central Advisory Board of Education (CABE) Commiitee on Sports and Physical Education has recommended that Physical Education and Sports should be a compulsory part of pre-ser-vice and in-service training of teachers and structural arrantremients slhnuld be made to get this prescribed in the teachers training courses. Regarding control over growth of sub-standard private colleges in Physical Education and Sports, the matter is under consideration..

Recommendations made in conference of vice-chancellors

8396. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have since received the proceedings and recommendations of the Conference of Vice-Chancellors held in 1993;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) The Conference of Vice-Chancellors was held in December, 1993, at New Delhi, to discuss the academic structure at the uiider-graduate level. The main recommendations made by the Conference in this regard are as under:—

(i) Improve the standard of under-graduate education.

(ii) Broaden knowledge by adding some courses, either Foundation Courses or Core Courses, on Environment, Population, Peace, International Understanding, Human Values, Moral Education, etc.

(iii) Introduce vocational components in the courses.

(iv) Simplify the evaluation pro cess to test the knowledge and skill of a student and adopt credit system in place of the present annual examination system or semester system.